Ephedrin HCL Tabs, Cloxacillin Sodidum, Amoxycillin Trihydrate, Potassium Iodide, Sodium Iodide apd

6 A. P. A.

जल-स्तर

2058. डा० अबरार अहमद खान: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नीचे जा रहे पानी के स्तर को रोकने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है और आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली जल के वितरण संबंधी योजनायें क्या क्या हैं?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाडिया) : भूजल विकास के नियंत्रण तथा विनियमन हेतु केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को एक माडल विधेयक अपनाने हेतु परिचालित किया है । अत्यधिक समुपयोजन के क्षेत्रों में भूजल विकास के संस्थागत वित्त पोषण पर प्रतिबंध लगाये गये हैं । देश में भूजल स्तरों की गिरावट को रोकने के लिये अन्य उपायों में ये शामिल हैं : वनरोपण, कंटूर बन्ध, नाला बन्द करना (नाला प्लगिंग) परिस्रवर्ग टैंकों का निर्माण तथा नवीकरण करना, भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण, उप-सतही भूजल बढ़ाने के बांध ।

इसके अलवा खेतों में जल के कुशल तथा किफायती वितरण के लिये कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम को 8वीं पंचवर्षीय योजना में भी जारी रखे जाने का प्रस्ताव है ।

इन्दिरा गांधी नहर

2059. डा० अबरार अहमद खान: क्या जल संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है और इस पर अभी तक कितनी धनराशि खर्च हो चुकी है और कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है ?

(ख) इस समय इससे कितनी भूमि की सिंचाई की जा रही है तथा इसके पूरा होने पर इससे कितनी भूमि की सिंचाई किये जाने की संभावना है ;

(ग) क्या यह रेगिस्तानी क्षेत्र के लोगों को पीने का पानी की समस्या को इस परियोजना के कार्यन्वयन द्वारा हल किया जा सकेगा ; और

(घ) क्या सरकार राजस्थान में रेतीली भूमि की सिंचाई एवं पेयजल की समस्या का स्थायी हल निकालने के लिये कोई योजना बना रही है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाडिया): (क) मुख्य लहर की संपूर्ण लम्बाई दिसम्बर 1986 तक पूरी हो गई थी । वितरण प्रणाली को शामिल करते हुये इंदिरा गांधी नहर परियोजना के चरण I तथा चरण II पर संभावित व्यय 31 मार्च, 1990 तक 723 करोड़ रुपये होगा । राज्य सरकार ने सूचित किया है कि निधियों के उपलब्ध होने पर परियोजना के दसवीं योजना तक पूरे होने की संभावना है और नहर कार्यों के लिये 1222 करोड़ रुपये की और राशि की आवश्यकता होगी ।

(ख) 5.65 लाख हेक्टेयर : पूर्ण विकास होने पर सिंचित क्षेत्र 13.88 लाख हेक्टेयर होगा ।

(ग) और (घ) रेगिस्तानी जिलों के भागों में परियोजना से पेयजल आपूर्ति तथा औद्योगिक प्रयोगों के लिये 34 घन मीटर प्रति सैकंड की व्यवस्था की गई है । 1.18 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र को सिंचाई तथा पेयजल प्रदान करने के लिये पहले से निर्माणाधीन इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अलावा सिद्धमुख तथा नोहर परियोजनाओं की तकनीकी-आर्थिक रूप से केन्द्रीय जल